

THE PARLIAMENTARY DEBATES OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND SEVENTY-THIRD

SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 13th February, 1995/24th Magha, 1916 (Saka)

RAJYA SABHA

Monday, the 13th February, 1995/24th Magha, 1916 (Saka)

The House met at thirty-eight minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

(The National Anthem was played)

PRESIDENTS ADDRESS—LAID ON THE TABLE

SECRETARY GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 13th February, 1995 [Placed in Library. See No. LT. 7004/95]

(Text of the Address deferred by the President (Dr. Shankar Dayal Sharma) in Hindi).

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूँ।

इस वर्ष आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए हैं। हमारी परिकल्पनायें काफी हद तक साकार हुई हैं, और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार की नई आर्थिक और अन्य नीतियों के फलस्वरूप देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। जनता ने सामाजिक स्थिरता के प्रति अपना विश्वास खुलकर व्यक्त किया है। राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को तथा विधि-सम्मत शासन जैसे मूलभूत मूल्यों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया है। हमारे देश ने विश्व-समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है, तथा अब हमारी अर्थ-व्यवस्था संसार से तेजी से विकसित हो रही

एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है।

वर्ष 1994-95 में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। देश में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ, तथा हिंसा की घटनाएँ भी अपेक्षाकृत कम रहीं। गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। सरकार सतर्क रहने के लिए कृतसंकल्प है—विशेष रूप से देश की एकता तथा अखण्डता के लिए संकट पैदा करने वाली अलगाववादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों के संबंध में।

अयोध्या मसले के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को जो मामला विचार के लिए भेजा गया था, उस पर उसने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय ने अधिग्रहण अधिनियम की वैधता को उचित ठहराया है, किन्तु निर्णयाधीनवादों के उप-शमन से संबंधित उपबन्धों का समर्थन नहीं किया है। विवादास्पद क्षेत्र अब केन्द्र सरकार के अधिकार में है, जिसे पुनः प्रवर्तित वादों का निपटान होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अब कानूनी रिसीवर के रूप में कार्य करना है। न्यायालय के निर्णय का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्णय में विवाद को वातचीत द्वारा सुलझाने की सम्भावना को भी स्वीकार किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सुधरे हुए वातावरण में इस विवाद का स्थायी समाधान हो जाए, और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि साम्प्रदायिकता के कारण राजनीति दूषित न होने पाए।

जम्मू व कश्मीर के मामलों के लिए प्रधान मंत्री के अधीन एक अलग विभाग का गठन किया गया है। राज्य में विश्वास तथा आर्थिक कार्य-कलापों की गति तेज करने के जोरदार प्रयास किए गए हैं। सरकार ने राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की है, और

इसकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित साधन मुहैया कराने के लिए वह नियमित रूप से इसकी जरूरतों का आकलन करेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित की जा रही हैं, तथा मतदाताओं की सूची संशोधित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग ने आरम्भ कर दिया है। उग्रवादियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। उग्रवादियों द्वारा अमरनाथ-यात्रा में व्यवधान डालने के प्रयासों को निफल करने में भी प्रशासन सफल रहा। निकट परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा का संयम से काम ले रहे हैं, तथा स्थानीय लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। राजनविकों और रासदों के शिष्टमंडलों ने राज्य का दौरा किया, और जनता के विभिन्न वर्गों से खुलकर बातचीत की। इन सतत और स्वच्छ प्रयासों से सर्वत्र विश्वास की भावना पैदा हुई है।

उत्तर-पूर्व में विद्रोही गतिविधियों से दृढ़तापूर्वक निपटने की अपनी नीति पर सरकार पूरी तरह अमल कर रही है। साथ ही इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि इन विघटनकारी तत्वों को हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मिजोरम की सरकार ने "हमारे पीपुल्स कन्वेंशन" के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। असम में भी इसी प्रकार उल्फा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

सितम्बर, 1994 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् का प्रावधान है। इस करार के प्रावधानों को शामिल करते हुए बिहार विधान सभा ने एक नया विधेयक पारित किया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे आंदोलन से उभरे मसलों के प्रति सरकार सचेत है, और उसका विश्वास है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा धैर्यपूर्वक और

सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करने पर समस्या का सर्वमान्य हल निश्चय निकल सकेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रहा है। सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की अपनी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।

आर्थिक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति हुई है। वर्ष 1994-95 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 4.3 प्रतिशत थी। 1994-95 की पहली छमाही में उत्पादन में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो औद्योगिक पुनर्जीवन का संकेत है। विदेशी मुद्रा का भण्डार 31 मार्च, 1994 को 15.1 बिलियन डालर था। किन्तु यह जनवरी, 1995 के अंतिम सप्ताह में बढ़कर 19 बिलियन डालर हो गया। सरकार नियत समय से पहले ही लगभग 1.1 बिलियन डालर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को लौटाने की स्थिति में थी। औद्योगिक क्षेत्र के पुनः सुदृढ़ स्थिति में आ जाने से आयात 23.9 प्रतिशत तक बढ़ गया है। निर्यात में भी डालर के रूप में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रुपए का मूल्य स्थिर रहा, और उसे चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया।

सरकार कीमतों में वृद्धि से चिन्तित है—विशेष रूप से सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से। कीमतों की स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने देने के उपाय किए जा रहे हैं। कुछ वस्तुओं; जैसे—चीनी और खाद्य तेल की कीमतें मुख्य रूप से अल्पाप्त घरेलू उत्पादन के कारण बढ़ी हैं। विदेशी मुद्रा की संतोषजनक स्थिति के कारण अधिक आयात करने से कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सहायता मिली है। भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूद अनाज के सार्वजनिक स्टॉक में से गेहूं व चावल की खुले बाजार में भी विक्री की गई है। आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली

एवं पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दिशा में आगे और प्रयास किए जायेंगे। देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराए जाते रहेंगे। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, सरकार पर्याप्त उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी, जिसमें गरीबों को अनिश्चित रियायतें दी जायेंगी।

उद्योगों को व्यापक रूप से नियंत्रणों से मुक्त करने का उद्यमियों ने शराहनीय स्वागत किया है। जुलाई, 1991 से अब तक 17,000 से भी अधिक निवेश संबंधी मंतव्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा, तथा इससे 34 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। लगभग 20 प्रतिशत निवेश संबंधी मंतव्यों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है, और अन्य 20 प्रतिशत प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनसे 14 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। हमारी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष 1994 में अप्रैल से दिसम्बर माह के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक राशि का संवितरण किया। इस दिशा में देश में जो पहल की गई, उससे विदेशी निवेशकों और सहयोगकर्तियों में भी निवेश के प्रति रुचि जागृत हुई है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय सान्नीदारों के कौशल और संसाधनों में जो विश्वास प्रकट किया है, वह इसी बात से स्पष्ट है कि विदेशियों ने संयुक्त उद्यमों में 80 प्रतिशत तक सीधे पूंजी निवेश किया है। वर्ष 1991 से आज तक प्रत्यक्ष विदेशी संचयी निवेशों की अनुमोदित राशि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गयी है। इसमें से अधिकांश राशि का निवेश लम्बी अवधि वाली आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में किया गया है। अन्य क्षेत्रों भी सुधार लाने और विनियमों में सुधार लाने की सरकार की नीति जारी

रही। नई औषधि नीति तथा दूरसंचार नीति इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र हमारी औद्योगिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उत्पादन स्तर 2 लाख 41 हजार 648 करोड़ रुपये है, जिससे 1 करोड़ 39 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले वर्ष इसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र द्वारा निर्यात की राशि लगभग 24,000 करोड़ रुपये है, जो कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्ग निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे 85 जिलों में; जहां लघु क्षेत्र इकाइयां संकेन्द्रित हैं, "सिंगल विंडो स्कीम" को अपनाना, और विशेष बैंक शाखाओं की स्थापना करना शामिल है। सरकार इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उदार-तापूर्वक सहायता देकर और अधिक बढ़ावा देगी।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने खादी और ग्रामीण उद्योगों को सुधारने, और पुनरुज्जीवित करने के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है, जिससे 20 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। एक विशेष रोजगार कार्यक्रम 50 चुने हुए जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा, तथा देश के 125 ब्लॉकों में गहन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। 2 अक्टूबर, 1993 से प्रारम्भ हुई प्रधान मंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अब इस वर्ष से इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारम्भ कर दिया गया है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम ने 2 लाख 30 हजार शिक्षित युवाओं का लाभ पहुंचेगा, जबकि पिछले वर्ष इससे 31 हजार 797 युवा लाभान्वित हुए थे। बैंकों ने 31 दिसम्बर, 1994 तक 69,483 उद्यमियों को ऋण मंजूर किए। सरकार 7 लाख युवकों को ऋण

प्रदान करेगी, जिससे आठवीं योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व रोजगार के 10 लाख अवसर प्राप्त होंगे।

पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का उत्पादन वर्ष 1994-95 में 78 लाख 20 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की आशा है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पोषक तत्व के रूप में फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन, जो वर्ष 1993-94 में 18 लाख 50 हजार मीट्रिक टन था, उसके वर्ष 1994-95 में बढ़कर 23 लाख मीट्रिक टन तक हो जाने की संभावना है। सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। पांच नए संयंत्रों में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने वाला है।

सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष 18 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन था, जिसके चालू वर्ष में बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। वर्ष 1993-94 में 15,100 करोड़ रुपये के कृषि ऋण का संवितरण किया गया। वर्ष 1994-95 में इस ऋण के 16,700 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 1994-95 में 27 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि के और सिंचित हो जाने की संभावना है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र बढ़कर 8 करोड़ 78 लाख 20 हजार हेक्टेयर हो जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1994-95 में उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 1 करोड़ 36 लाख मीट्रिक टन होगी, जो कि वर्ष 1993-94 की खपत की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी और मत्स्य उद्योग जैसे व्यवसायों से अधिक आय अर्जित कराने के लिए विविध योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बागवानी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए केवल 24 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। वर्ष 1993-94 में मत्स्य उत्पादन 46

लाख 80 हजार मीट्रिक टन था, जो कि अपने आप में अब तक का एक रिकार्ड है। वर्ष 1994-95 में इसका उत्पादन 47 लाख 50 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। पिछले पांच वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में तीन गुणा वृद्धि हुई है।

सरकार के विकास संबंधी समस्त प्रयासों का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण विकास है। सुस्पष्ट लक्षित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की रोजगार नीति के आधारस्वरूप हैं। पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय योजना के आबंटन में निरन्तर वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में इस कार्य के लिए 7,010 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं, जो हमारी योजना के इतिहास में अब तक आबंटित सर्वाधिक राशि है। इतनी बड़ी राशि के परिव्यय से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होंगे, तथा बड़े पैमाने पर संस्थागत वित्त जुटाकर स्व-रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5,055 करोड़ रुपये का प्रावधान है। चालू वर्ष में रोजगार आश्वासन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को बढ़ाकर देश के सबसे अधिक पिछड़े 2,279 क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि पहले यह केवल 1,778 ब्लकों में था। जवाहर रोजगार योजना के अतिरिक्त एक गहन रोजगार योजना कार्यक्रम लम्बे अरसे से 120 पिछड़े जिलों में चल रहा है। इन सभी योजनाओं से चालू वर्ष के दौरान रोजगार के 147 करोड़ श्रम दिवस उपलब्ध होने की संभावना है।

परिसंपत्ति एवं ऋण पर आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष से लगभग 20 लाख गरीब ग्रामीण परिवार स्व-रोजगार पा सकेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर की ऋण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित किया जा रहा है, तथा

प्रति परिवार औसत निवश को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जा रहा है। 1,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए का संस्थागत ऋण जुटाया जाएगा। ये कार्यक्रम ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग की आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से महिला ग्रुपों को अब तक दी जाने वाली 15,000 रुपए की राशि के स्थान पर 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर सक, और साक्षरता एवं परिवार कल्याण जैसे कार्यों को ग्रुपों में करने की प्रवृत्ति विवसित हो सके। इससे महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा।

अप्रैल, 1994 तक की निर्धारित अवधि में सभी राज्यों ने अपने मौजूदा पंचायती राज कानूनों को संशोधित कर लिया है, या नए कानून बना लिए हैं। अब यह आवश्यक है कि सभी जगह चुनाव कराए जाएं, और सभी स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाए। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। मैं सभी राज्यों का आह्वान करता हूँ कि वे पंचायती राज की चुनाव प्रक्रिया अविरोध कर लें।

सरकार शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव करती है। इस कार्यक्रम में शहरों के सभी प्रकार के कूड़ा-करकटों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाना भी शामिल है। इस कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वयंसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा। सरकार देश के 50,000 से एक लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी-II के 345 शहरों के लिए एक योजना बनाने पर विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया

उत्साहजनक रही है। इस दिशा में राज्यों के प्रयासों की गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष राज्यों को 273 करोड़ 85 लाख रुपए आवंटित किए हैं। पिछले वर्ष सफाई कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्त कराने, तथा उनके पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आयोग प्रशिक्षण देने, अधिकाधिक संस्थागत वित्त जुटाने जैसे पुनर्वास कार्यक्रम चलायेगा तथा यूनिट लागतों के परिवर्धन की आवश्यकता पर विचार करेगा।

“राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम” के माध्यम से बांजिन राशि और ऋणों का प्रावधान करके गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, तथा उनका विस्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस क्रम में इसकी अधिस्त शेरर पूंजी 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है।

भारत सरकार ने सितम्बर, 1993 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की दिशा में पहला कदम उठाया था, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका पूरा लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को मिले, सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित मानकों में ढील दी है, जिस प्रकार की सुविधा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप वर्ष 1994 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के 1,873 अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की। सरकार ने आयु में तीन वर्ष की छूट देने के नियम को लागू करने, तथा इस परीक्षा के लिए तीन अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के क्रियाकलापों को बढ़ावा

बेने, तथा उनके तकनीकी ज्ञान एवं उद्यम-कौशल के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने सितम्बर, 1994 से कार्य आरम्भ कर दिया है। चालू वर्ष में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 25 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रतिष्ठान ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे स्तलों में जहां साक्षरता कम है, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोलेगा।

सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ नए उपायों पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत एक आयोग के गठन पर विचार किया जा रहा है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे जन-जातीय उपयोजना तथा अन्य उपायों की समीक्षा करेगा, ताकि इनकी कार्य नीतियों में सुधार लाया जा सके, शिक्षा, आवासीय प्रशिक्षण तथा रोजगार नियोजन जैसे क्षेत्रों में विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाएं तथा मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए न्यास बनाया जा सके।

महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों में सरकार का दृष्टिकोण ऐसी अनुकूल नीतियां तैयार करने का रहा है, जिनमें योजना का केन्द्र बिन्दु महिलाएं एवं बच्चे और विशेषकर बालिकाएं हों। इस योजना में महिलाओं को सक्षम बनाने, समर्थन सेवाएं प्रदान करने, तथा पोषण कार्यक्रम चलाने का प्राथमिकता दी गई है। इस बारे में उल्लेखनीय उपलब्धियों में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाना, राष्ट्रीय पोषण परिषद् और राष्ट्रीय शिशुगृह निधि की स्थापना करना तथा महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन शामिल है। महिला समृद्धि योजना को काफी लोक-

प्रियता मिली है। दिसम्बर, 1994 तक 72 लाख खाते खोले जा चुके थे, जिनमें कुल जमा राशि 65 करोड़ 90 लाख रुपए थी। 8वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय शिशुगृह निधि से सेवारत महिलाओं और बीमार माताओं के 45,000 बच्चों की दिन में देखभाल करने के लिए 1,800 अतिरिक्त शिशुगृह खोलने में सहायता मिलेगी।

पूरे देश में एकीकृत बालविकास सेवा कार्यक्रम लागू करने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान प्रथम उपाय के रूप में सामुदायिक पोषण केन्द्रों के माध्यम से 1 लाख गांवों में 1,000 नए लार्कों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

मनु 2,000 तक "सभी को शिक्षा" प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार शिक्षा पर खर्च की राशि को उत्तरात्तर बढ़ाएगी, ताकि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। देश में इस समय 312 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें 9 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रारंभ होने से अब यह लगने लग है कि सार्वभौम प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

मनु 2,000 तक जोखिमपूर्ण उद्योगों में तथा सभी प्रकार के रोजगारों में क्रमिक रूप से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार कृतसंकल्प है। शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा श्रम जैसे विकास प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों की कार्यवाई का समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें ऐसे एकीकृत कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे, जिनसे बालकों को रोजगार से निकालकर निश्चित रूप से स्कूलों में दाखिल कराने के लिए अनुकूल स्थितियां बन सकें।

आज हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप से लागू करने के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पोलर सैट-

लाइट लांच व्हीकल) डी 2 तथा संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ग्रॉमन्टेड सैट-लाइट लांच व्हीकल)-ए० एस० एल० वी. डी4 से यह स्पष्ट हो गया है कि हम ध्रुवीय तथा पृथ्वी की समीपवर्ती कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इनसैट श्रेणी के हमारे उपग्रह दूर-संचार, दूरदर्शन-प्रसारण, मौसम तथा विनाश संबंधी चेतावनी जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस बृखला में आगामी उपग्रह इनसैट 2 सी, तथा दूरसंचारी सीरीज उपग्रह-आई० आर० एस० 1 सी वर्ष 1995 में छोड़े जाने की योजना है। यह वर्ष की बात है कि एशिया प्रशान्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत का चयन किया गया है।

अपनी भाषा में कार्यक्रम देखने की जन अभिलाषा पूरी करने के उद्देश्य से दूर-दर्शन ने अपनी उपग्रह सेवा में अनुकूल परिवर्तन कर लिया है। 14 चैनलों में 11 उपग्रह चैनल अब केवल क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए हैं।

देश परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने का लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में डिजाइन किया गया एवं बना छठा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर तैयार हो गया है, जो ककरापार परमाणु शक्ति स्टेशन की दूसरी इकाई है। इसने इस वर्ष 8 जनवरी को काम करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार देश ने इस उन्नत प्रौद्योगिकी में एक बार फिर आत्मनिर्भरता का प्रमाण दिया है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और भी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे-नाभिकीय ग्रेड ग्रेफाइट का उत्पादन, मैडिकल लेसर का निर्माण तथा समानान्तर सुपर कंप्यूटर का विकास आदि।

हमारी सशस्त्र सेनाएं हमारी अंतर-राष्ट्रीय सीमाओं तथा समुद्री हितों की रक्षा करने में सतर्क रही हैं। उन्होंने जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में विद्रोह को दबाने के कार्य में बड़ा योगदान दिया है।

हमारी स्थल सेना ने, भारतीय वायुसेना और नौसेना के कौशलपूर्ण सहयोग से सोमालिया में शान्ति बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में अपने योगदान के लिए, विशेष रूप से युद्धरत सेनाओं को पीछे हटाने में जो सफलता प्राप्त की है उसकी विदेशों में भूरि-भूरि सरहना हुई है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने की दिशा में पिछला वर्ष संतोषजनक रहा। पूरे विश्व में मौजूदा मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, और हमारे उद्देश्यों एवं नीतियों के प्रति नई समझ पैदा हुई है।

संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हमारा निरन्तर समर्थन रहा है, क्योंकि यह मानवता के समान लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो पहल की हैं, उसमें विश्व संगठन का लोकतंत्रीकरण तथा समसामयिक वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाना शामिल है। हमने शीतयुद्ध के बाद को विश्व सुरक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए चौथे विशेष निरस्त्रीकरण सत्र का प्रस्ताव रखा है।

हम अगले वर्ष अप्रैल में अपने देश में अगला सार्क-सम्मेलन करेंगे, तथा क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

पिछले वर्ष हमने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की और निरन्तर ध्यान दिया है। हम उन नई सरकारों का स्वागत करते हैं, जो श्रीलंका तथा नेपाल में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई हैं। हम उनके साथ, तथा अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध और अभिकाधिक सहयोग चाहते हैं।

परन्तु खेद की बात है कि पाकिस्तान अभी भी भारत के साथ टकराव के मार्ग पर चल रहा है और हमारे अंदरूनी मामलों

में उसका अनुचित हस्तक्षेप जारी है। हमने दोनों देशों के बीच अनुसुलझ मुद्दों का शिमला समझौते के अनुसार सुलझाने की दिशा में बार-बार पहल की है। बात-चीत के लिए हमारी पेशकश अभी भी बरकरार है। हमें खद है कि इस बीच पाकिस्तान ने बम्बई में अपना कार्यालय तथा कराची में भारतीय महाकांसुलावास बंद करने के इकतरफा कदम उठाए हैं। ऐसा करके उसने लोगों के आपसी संपर्क और वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संबंधों में और अधिक रुकावटें पैदा की हैं।

सरकार ने अपने पुराने और नये विदेशी मित्रों के साथ पारस्परिक समझ और सहयोग सुदृढ़ करने के प्रयास किए हैं। बल्गारिया और रूमानिया की मरी राजकीय यात्राओं से व घनिष्ठ संबंध फिर स ताजे हुए हैं, जो भारत तथा पूर्वी यूरोप के देशों के मध्य अनेक दशकों से चले आ रहे हैं।

हमारे उप-राष्ट्रपति ने आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन की यात्रायें कीं, और इन यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वियतनाम और सिंगापुर की यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंधों को हर क्षेत्र में बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

अमेरिका की यात्रा से दोनों देशों के महत्वपूर्ण मसलों को आपस में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सका है, और इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही नहीं; बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी परस्पर आदान-प्रदान को फिर से आगे बढ़ाने का आधार मिला है।

प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, वियतनाम तथा सिंगापुर की यात्रायें इस बात का प्रमाण हैं कि हम अपने यूरोपीय तथा

एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के इच्छुक हैं।

पिछले वर्ष के दौरान भारत-रूस संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं, और उनमें गति आई है। राष्ट्रपति येल्तसिन और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बहुवादी राज्यों के हितों की सुरक्षा संबंधी मास्को घोषणा दोनों देशों के संबंधों में एक उल्लेखनीय योगदान है।

हमने हाल ही में इस वर्ष के अपने गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया। उनकी यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है।

हमारे आर्थिक प्रबंधों की सफलता; जिस पर हमारे देशवासियों की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, तथा आर्थिक उद्घारीकरण के परिणामस्वरूप हुए लाभकारी परिवर्तनों को विदेशों में कारगर ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे प्रयासों की विदेशों में बहुत ही अनकल प्रतिक्रिया हुई है।

इन नीतियों के कारण देश में जो गतिशीलता आई है, उसे बनाए रखना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लाभ मिलने शुरू हुए हैं, उन्हें हम गंवा न दें। हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति निवेश-कर्तृताओं का और आर्थिक सुधारों के प्रति जनता, विशेषरूप से विशेषाधिकारहीन जनता, का विश्वास दृढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। संसद में बहस के दौरान आपके शब्द और विचार इन दोनों बातों को प्रतिफलित और प्रभावित भी करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन उद्देश्यों पर उचित ध्यान देते हुए अपने काम में अग्रसर होंगे। कार्यक्रम के लिए आपका आह्वान करते हुए मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द ।।

[English version of the Text of the Address delivered by the President (Dr. Shankar Dayal Sharma)]
Hon'ble Members,

I welcome you to this Session of Parliament.

As I stand to address you this year I note that the optimism and self-assurance evident last year has been vindicated. The projections made have been fulfilled in substantial measure and it can be said with confidence now that the country has made the turnaround initiated by the new economic and other policies of the Government. The people have responded handsomely by reasserting their faith in social stability. Political parties have also contributed to strengthening democracy and fundamental values such as the rule of law. Our country has improved its standing in the global community and now stands poised to become one of the rapidly growing economies of the world.

The law and order situation continued to be under control in 1994-95. There was no major communal riot in the country and incidents of violence were fewer. Polls in Goa, Sikkim, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have been peaceful. Government is determined to be watchful, particularly in respect of the secessionist and communal forces that pose a threat to the unity and integrity of the country.

On the Ayodhya issue, one of the noteworthy developments is that the Supreme Court delivered its judgement on the reference made to it. It has upheld the validity of the Acquisition Act, but not the provisions relating to abatement of the pending suits. The disputed area is vested in the Central Government which is now to act as a statutory receiver for maintaining the status quo until the disposal of the revived suits. Compliance with the decision of the Court is essential. The judgement recognises the possibility of a resolution

of the dispute through negotiations. It is of utmost importance that the improved atmosphere leads to a lasting solution to this dispute and we collectively ensure that communalism does not vitiate politics.

A separate Department of J & K Affairs has been set up under the Prime Minister. Vigorous efforts have been made to step up the pace of the development and economic activity in the State. Government has ensured availability of adequate funds to the State and will regularly assess its needs sympathetically, in terms of the resources required for its developmental needs. The objective of revival of the democratic process is also being pursued. The delimitation of constituencies is being done and the work of revision of the voters' list has been taken up by the Election Commission. Operations against militants are being intensified. The attempts by militants to disrupt the Amarnath Yatra were successfully foiled by the administration. In spite of the trying conditions, the security forces are showing restraint and are sensitive to the feelings of the local people. Delegations of diplomats and Parliamentarians visited the State and interacted freely with various sections of the people. This continuing transparency has generated over-all confidence.

In the North-East, Government is pursuing its policy of dealing firmly with insurgent activities. At the same time, efforts are being made to encourage these disruptive elements to abjure violence and join the national mainstream. The Government of Mizoram signed an Accord with Hmar Peoples Convention resulting in surrender of militants. There has been similar surrender by ULFA militants in Assam.

An agreement was signed in September, 1994 providing for a Jharkhand Area Autonomous Council. A new Bill incorporating the provisions of the agreement has been passed by the Bihar Assembly.

Government is seized of the issues that have arisen in the hill areas agitation in Uttar Pradesh and is confident that given patience and sympathetic handling by all concerned, acceptable solutions will be found.

The National Human Rights Commission carried on its work with dedication. Government stands committed to its policy of promotion and preservation of human rights.

The economic reforms have brought about an upswing in the economy. During 1994-95, the gross domestic product, at constant prices, is expected to increase by 5.3 percent, as against 4.3 percent last year. Industrial revival started with an 8 percent increase in production in the first half of 1994-95. Foreign Exchange reserves rose from \$ 15.1 billion on 31.3.94 to over \$ 19 billion in the last week of January, 1995. Government was in a position to repay about \$ 1.1 billion to the IMF ahead of schedule. As a consequence of the strong revival of the industrial sector, imports increased by 23.90 percent. Exports have also grown by 16.9 percent in dollar terms. The rupee continued to remain stable and was convertible on Current Account.

Government is concerned about the increase in prices, especially of articles of mass consumption. The price situation is being watched closely and measures are being taken to prevent shortages. In the case of some commodities, like sugar and edible oil, prices had risen mainly due to insufficient domestic production. The comfortable foreign exchange position has enabled imports to augment supplies and control the rise in the prices. In the case of wheat and rice, open market sales out of public stocks of foodgrains held by the Food Corporation of India have also been undertaken. The Public Distribution System and Revamped Public Distribution System are also being used to provide assistance in making essential

commodities available. Further efforts will be continued in this direction. Remunerative minimum support prices would continue to be assured to the farmers to safeguard the country's food security. As far as essential commodities are concerned, Government will pursue the twin objectives of ensuring adequate availability and fair prices, with extra concessions for the poor.

The wide ranging industrial de-regulation has evoked commendable response from entrepreneurs. More than 17,000 investment intentions have been filed since July, 1991 totalling investment of over Rs. 3,50,000 crores with potential for direct employment for 3.4 million persons. Nearly 20 percent investment intentions have so far been implemented and another 20 percent are at various stages of implementation. These are estimated to generate direct employment to the extent of 1.4 million persons. Disbursements by our major financial institutions from April to December, 1994 have shown a 39 percent increase over the same period in the previous year. The growth of domestic initiative has generated interest amongst foreign investors and collaborators. The confidence exhibited by foreign investors in the skills and resources of Indian partners is evident from the large foreign direct investment in joint ventures to the extent of 80 percent. Cumulative foreign direct investment approvals since 1991 have exceeded Rs. 20,000 crores, the bulk of it in long gestation infrastructure projects. Government continued with its policy of reforms and de-regulation in other sectors. The new Drug Policy and the Telecom Policy are steps in this direction.

The small scale sector is an important component of our industrial base, its production level being Rs. 2,41,648 crores and generating an employment of 139 lakh persons. It recorded a growth of 7.1 percent last year. Exports from this sector are around

Rs. 24,000 crores, accounting for nearly 35 percent of total exports. To meet the credit needs of this sector, the Reserve Bank of India had issued guidelines including the adoption of a single window scheme in 85 districts where small scale units are concentrated, and setting up of specialised bank branches. Government will enhance support to this sector further through liberal assistance for technology upgradation.

A high power committee under the Chairmanship of the Prime Minister has adopted an action plan for revitalising and improving khadi and village industries and generate additional employment for 2 million persons. A special employment programme would be undertaken in 50 selected districts and intensive development of 125 blocks in the country would be promoted.

Employment for the educated youth is a prime concern of the Government. The Prime Minister's Rozgar Yojana which is being implemented from 2nd October, 1993, was designed to provide self-employment for youth in the urban areas. It has been now extended to cover the rural areas also from this year. During the current year, 2.3 lakh educated youths will benefit from this programme, as against 31,797 last year. Banks have sanctioned loans to 69,483 entrepreneurs till 31st December, 1994. Government will provide loan to 7 lakh youths to generate 10 lakh employment opportunities before the end of the 8th Plan period.

The production of nitrogenous fertilizers is expected to reach an all time record of 78.2 lakh tonnes in 1994-95, in terms of nutrients. Production of phosphatic fertilizers is expected to increase from 18.5 lakh tonnes in 1993-94 to 23 lakh tonnes in 94-95 in terms of nutrients. Government has continued with its efforts to increase the domestic production of fertilizers with five new plants

likely to commence production shortly

Government has continued to give high priority to the development of the agriculture sector. The production of foodgrains is expected to increase from 182 million tonnes last years to 185 million tonnes in the current year. Disbursement of agricultural credit was Rs. 15,100 crores during 1993-94, and is expected to reach a level of Rs. 16,700 crores during 1994-95. The area covered under irrigation is expected to go up by 2.77 million hectares in 1994-95 bringing the total area under irrigation to 87.82 million hectares. The consumption of fertilizer nutrients during 1994-95 is estimated at 136 lakh tonnes showing an increase of about 10 per cent over the consumption of 1993-94.

Government has been promoting diversification schemes in rural areas to provide higher incomes from occupations like horticulture and fishing. Accordingly, horticulture has been given an outlay Rs. 1000 crores in the current Five Year Plan as against an outlay of only Rs. 24 crores in the last Five Year Plan. Fish production, which recorded an all time high of about 46.8 lakh tonnes in 1993-94, is likely to reach a level of 47.5 lakh tonnes during 1994-95. There has been a three-fold increase in export of agricultural products during the last five years.

Rural development is the central concern of all the developmental efforts of the Government. Sharply targeted rural development programmes underpin its employment strategy in poverty eradication. The central plan allocations for rural development schemes have been progressively enhanced during the last three years and the current year's allocation of Rs. 7,010 crores is the highest ever in our planning history. This large outlay goes to provide additional wage employment as well as self-employment through mobilisation of institutional finances on a

large scale Rs. 5,055 crores go to provide employment through the Jawahar Rozgar Yojana and the Employment Assurance Scheme. For the Employment Assurance Scheme an amount of Rs. 1,200 crores has been earmarked during the current year. This programme has been expanded from 1,778 most backward blocks of the country to 2,279 blocks in the current year. In addition to the Jawahar Rozgar Yojana, an intensive JRY Programme focuses on 120 chronically backward districts. All these schemes together are expected to generate 1,470 million mandays of employment in the current year.

The asset-cum-loan based Integrated Rural Development Programme which provides self-employment would cover about 2 million rural poor households from this year. The district and block level credit plans are being coordinated more effectively and the average investment per household is being increased to Rs. 12,000. Rs. 2,000 crores of institutional credit would be mobilised through a subsidy of Rs. 1098 crores. These programmes will increasingly cater for the rural literate youth. Simultaneously, the Programme for the Development of Women and Children in Rural Areas is being extended to all the districts and will now provide Rs. 25,000 against Rs. 15,000 hitherto, to women's groups to help them pursue economic activities and enhance group action in matters like literacy and family welfare, leading to women's empowerment.

As stipulated, by April, 1994; all States amended their existing Panchayati Raj laws or have legislated new laws. Now it is necessary to hold elections and constitute Panchayats at all levels. Some States have already made a beginning. In order to fulfil the high expectations of the people, the Panchayats must be empowered with financial and administrative delegation. I call upon all the

States to complete the Panchayat electoral process without delay.

Government recognises the need for an integrated programme to deal with the problems of urban poverty. This programme would include scientific disposal of urban wastes of all kinds. Voluntary organisation would be fully involved in its design and implementation. Government is seeking to formulate a scheme for 345 Class II towns of the country that have populations ranging from 50,000 to 1 lakh.

The response from the State to the Special Component Plan for the Scheduled Castes has been encouraging. The Central allocation to States to supplement their efforts this year in Rs. 273.85 crores. An important step taken last year was the constitution of the National Commission for Safai Karmacharis, to oversee the programmes aimed at the liberation and rehumiliation of the Safai Karmacharis. The Commission would address itself to rehabilitation programmes such as training, better mobilisation of institutional finances and the need for enhanced unit costs.

Efforts to strengthen and expand economic support programmes to the poor by the provision of margin money and loans through the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, have been stepped up as has been its authorised share capital from Rs. 125 crores to Rs 300 crores.

The first step in providing for reservation of 27 per cent for the OBCs under the Government of India was taken in September, 1993 and is under implementation. In order to ensure that the full benefits of this measure are available to the OBCs, Government relaxed the standards required for OBC candidates to be on par with the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates and as a result, 1,873 additional OBC candi-

dates qualified for the Civil Services Preliminary Examinations, 1994. Government has also decided to extend the 3 years' age relaxation principle and to allow 3 additional attempts.

The National Minorities Development and Finance Corporation became operational in September, 1994 with an authorised share capital of Rs. 500 crores to promote the economic development activities of the backward sections amongst the minorities and to assist the upgradation of their technical and entrepreneurial skills. An amount of Rs. 25 crores has been provided during the current year to the Maulana Azad Education Foundation. The Foundation will set up residential schools for girls in low literacy slum and rural areas.

Certain new measures are under consideration of the Government for the protection of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the disabled. These are inclusion of the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and the Protection of Civil Rights Act, 1955 in the IX Schedule of the Constitution, setting up of a Commission under Article 399(1) of the Constitution to review the development strategies like the Tribal Sub Plan and other measures presently in operation for the welfare and development of the Scheduled Tribes so as to improve upon these strategies, legislation to provide equal opportunities to the handicapped in areas like education, vocational training and employment placements, and a Trust for the Welfare and protection of the mentally retarded.

In matters relating to women and children, Government's approach has been to provide an enabling policy environment in which their concerns, particularly those of the girl child, are the central focus of planning. Priority is given to the empowerment of women, support services and nutrition programmes. The noteworthy achievements in this process have been the adoption of the National

Nutrition Policy, the setting up of the National Nutrition Council and the National Creche Fund and implementation of the Mahila Samridhi Yojana. The Mahila Samridhi Yojana has had an impressive response. By December, 1994, 72 lakh accounts had been opened with a total deposit of Rs. 65.90 crores. The National Creche Fund will assist in starting 1800 additional cheques by the end of the 8th Plan to provide day care services to 45,000 children of working women and ailing mothers.

As part of the effort at covering the entire country with the Integrated Child Development Services Programme, it is proposed to cover 1000 new blocks through Community Nutrition Centres in one lakh villages, as a first step, during 1995-96.

To achieve the goal of Education for All by 2000 AD, Government will progressively raise the allocation to education so as to reach the target of 6 per cent of GDP. Total Literacy Campaigns are now operational in 312 districts in the country covering about 50 million learners in the 9-45 years age group. With the emergence of Total Literacy Campaigns, it is now being perceived that universal adult literacy is an achievable task.

The Government is determined to eradicate Child Labour progressively in all employments and, in hazardous industries, by the year 2000 AD. A National Authority for Elimination of Child Labour has been set up co-ordinate actions of the core sectors of development administration such as education, rural development, women and child development, health and labour to devise integrated programmes that would bring about conditions conducive to withdrawal of children from employment and place them family in schools.

We are today in the forefront in the practical application of the space technology in vital areas. The Polar Satellite Launch Vehicle D2 and

the Augmented Satellite Launch Vehicle—ASLV D4 demonstrated our capacity to place satellites into polar and near earth orbits. Our INSAT class of satellites are providing services in telecommunication, TV broadcasting, meteorology and disaster warning. The next satellite in this series, INSAT 2C, and the remote sensing series satellite, IRS, IC are planned for launch in 1995. It is heartening to note that India has been selected for the setting up of a UN Centre for Space Science and Technology Education to cater to the needs of the Asia Pacific region.

To meet the aspirations of the people to view programmes in their own language, Doordarshan has reconfigured its satellite service. Out of 14 channels, 11 satellite channels are now exclusively for programmes in regional languages.

The country continued to make strides in its efforts to harness the power of the atom for peaceful purposes. With the completion of the sixth Indian designed and constructed nuclear power reactor — the second unit of the Kakrapar Atomic Power Station, which achieved criticality on January 8 this year — the country once again proved its self-reliance in this advanced technology. There were also spin-offs from the use of nuclear technology, such as the production of nuclear-grade graphite, fabrication of medical lasers and development of parallel supercomputers.

Our Armed Forces maintained their vigilance in defending our international borders and maritime interest. They also made valuable contributions in counter-insurgency operations in Jammu & Kashmir and in the North-East.

Abroad, the Army won plaudits for its contributions to the UN peace-

keeping effort in Somalia, ably supported by the Indian Air Force and Navy, especially in the de-induction of forces.

In the conduct of international relations, we can view the past year with satisfaction. Existing friendships were reinforced and new understanding created around the world of our objectives and policies.

Our continuing support for the United Nations, which observes its 50th anniversary this year, is based on the premise that it is the most effective instrument for the realisation of humanity's common goals. India's initiatives at the United Nations included the need for the democratisation of the world body and the enlargement of the UN Security Council's membership to reflect contemporary realities. We proposed a Fourth Special Session on Disarmament to address post-Cold War issues of global security.

In our own region, we will be hosting the next SAARC Summit in April this year and look forward to working with our SAARC colleagues to further strengthen regional co-operation.

During the past year, closer bilateral relations with our neighbours continued to secure our attention. We welcome the new Governments which assumed office in Sri Lanka and Nepal through multi-party democratic elections. We look forward to closer understanding and increasing co-operation with them, as with all our other neighbours.

Pakistan has however continued on its distressing path of confrontation with India and unacceptable interference in our internal affairs. We have taken repeated initiatives with Pakistan to settle all unresolved issues between our two countries according to the Shimla Agreement. Our other of such a dialogue still stands. Meanwhile we regret the unilateral steps

taken by Pakistan to close their office in Bombay and the Indian Consulate General in Karachi, thereby creating greater barriers to people-to-people contacts, and commercial, cultural and other relations.

The Government has worked to consolidate understanding and cooperation with old and new friends abroad. My State visits to Bulgaria and Romania renewed the close ties that have existed for decades between India and countries of Eastern Europe.

Our Vice-President visited Australia, South Africa and China and the visits reinforced our ties with the countries.

The Prime Minister's visits to the United Kingdom, USA, Russia, Vietnam and Singapore contributed significantly to the all round enhancement of our ties with them.

The visit to the USA, which resulted in greater mutual understanding on matters of concern to the two countries, opened a new chapter in bilateral relationship. It laid the groundwork for resurgent India-US interaction not only in the political, economic and commercial fields but in other areas as well.

The Prime Minister's visits to the United Kingdom, Vietnam and Singapore testified to our desire to reinforce ties with our European and Asian partners.

India-Russia ties gained in substance and momentum during the last year. The Moscow Declaration on the Protection of the Interests of Pluralistic States signed by President Yeltsin and our Prime Minister was a notable contribution to the conduct of inter-state relations.

We recently welcomed President Nelson Mandela of South Africa as the Chief Guest for our Republic Day celebrations this year. His visit marks a new chapter in the building up of

India-South Africa cooperation in various fields.

Our efforts to effectively project abroad the success of our economic management, on which depends the well-being of our people, and the beneficial changes that have taken place as a result of economic liberalisation, have received excellent response in countries abroad.

The momentum gathered by the country through these policies has to be sustained to ensure that the benefits that have started accruing are not frittered away. A combined effort is necessary to strengthen the confidence of investors in our economy and of the people, particularly the underprivileged, in the economic reforms. The tone and tenor of your debates reflect and greatly influence both. I am confident you will set the pace with due regard to these objectives. I commend you to your tasks and wish you success. JAI HIND

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I refer with profound sorrow to the sad demise of Giani Zail Singh, former President of India and a veteran of our freedom struggle, on 25th December, 1994. Gianiji was born in May, 1916 at Sandhwan village of Faridkot district of Punjab. Gianiji joined the freedom movement while he was still in his teens. He took an active part in the movement against princely aristocracy and autocratic rule of the Maharaja of Faridkot. He was arrested in 1936 and subsequently courted arrest on numerous occasions during the freedom struggle. He led the National Flag agitation at Faridkot in 1946. It can never be forgotten that Giani Zail Singh underwent a sentence of five years' rigorous imprisonment in solitary cell for his activities as a freedom fighter.